ब्रज किशोर ठाकुर

बनाम

भारत संघ और अन्य

24 फरवरी 1997

[मदन मोहन पुंछी और के. टी. थॉमस, न्यायमूर्तिगण]

न्यायिक संयम: जिला और सत्र न्यायमूर्ति द्वारा जमानत दी गई - उत्तरदाता ने जमानत आदेश को चुनौती दी - उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश रद्द कर दिया और जिला और सत्र न्यायमूर्ति के खिलाफ कड़ी टिप्पणियाँ करते हुए कहा कि, "जमानत देने का कार्य बाहरी विचारों के लिए था" और "वह सत्र न्यायमूर्ति बने रहने के लायक नहीं हैं और उन्हें उनकी मूल शक्तियों से वंचित कर देना चाहिए" - फैसला, टिप्पणियाँ अनुचित थीं और इसलिए हटा दी गईं - भारत का संविधान अनुच्छेद 136 अभ्यास और प्रक्रिया - जिला और सत्र न्यायमूर्ति द्वारा पारित न्यायिक आदेश - कारण - उच्च न्यायालय ने आदेश के समर्थन में कारण बताते हुए प्रतिवेदन मांगी - फैसला, यह एक अस्वास्थ्यकर प्रथा है और इसलिए इसकी निंदा की गई।

अपीलकर्ता-ज़िला न्यायमूर्ति ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20(ख)(i) के तहत अपराध में शामिल दो लोगों को ज़मानत दे दी। उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय में ज़मानत के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायमूर्ति ने ज़िला और सत्र न्यायमूर्ति से अभिलेख और प्रतिवेदन मंगवाई और उन्हें देखा। इसके बाद, उन्होंने ज़मानत का आदेश रद्द कर दिया, और अपीलकर्ता के खिलाफ़ कड़ी टिप्पणियाँ भी कीं, यह कहते हुए कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों को नज़रअंदाज़ करके ज़मानत देना न्यायिक लापरवाही थी और ज़मानत बाहरी कारणों से दी गई थी और वह सत्र न्यायमूर्ति बने रहने के लायक नहीं हैं और उन्हें उनकी

मूल शक्तियों से वंचित कर देना चाहिए। इस आदेश से दुखी होकर, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति से यह अपील दायर की।

अपील का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने

फैसला सुनाया: 1. इस वाद में, सेशंस न्यायमूर्ति अपने क्षेत्राधिकार में थे जब उन्होंने दोनों व्यक्तियों को जमानत देने का आदेश पारित किया, हालांकि यह एक अलग बात है कि क्या उन्होंने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया था। जब एकल न्यायमूर्ति ने अधीनस्थ न्यायालय के एक ऐसे न्यायमूर्ति पर, जिसका कोई बचाव करने वाला नहीं था, अनुचित, अप्रिय और तीखी टिप्पणियां कीं; तो वह सिर्फ न्यायपालिका की संस्था को चोट पहुंचा रहे थे। इसलिए, न्याय और निष्पक्षता के हित में एकल न्यायमूर्ति द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटा दिया जाता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम किशन लाल, एआईआर [1991] एससीसी 558, संदर्भित किया गया।

2. न्यायिक संयम एक गुण है। एक ऐसा गुण जो हर न्यायिक अभिव्यक्ति के साथ होना चाहिए। यह एक न्यायमूर्ति का गुण है जिसे उसे समय-समय पर बनाए रखना होता है, खासकर जब वह अपने सामने आने वाले मामलों से निपट रहा हो, चाहे वह अपीलीय या पुनरीक्षण या अन्य पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा हो। उच्च न्यायालयों को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि न्यायिक पदानुक्रम में उच्च स्तर इसलिए प्रदान किए गए हैं ताकि अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों या आदेशों में संभावित त्रुटियों को ठीक किया जा सके। ऐसी शक्तियां निश्चित रूप से निचले स्तर के न्यायिक व्यक्तियों पर कटु आलोचना करने के लिए नहीं हैं। [422-सी-डी]

काशीनाथ बनाम बिहार राज्य, जेटी (1996) 4 एससी 605; *के.पी. तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* एआईआर (1994) एससी 1031 और *इसुहारी प्रसाद मिश्रा बनाम मोहम्मद इयास,* [1963] 3 एससीआर 722, पर भरोसा किया गया।

कमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य, **(1994) 2 पीएलजेआर 600, का हवाला दिया गया।**

3. न्याय प्रशासन तथा न्यायिक संस्थानों में लोगों के भरोसे को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, जितनी तब पहुँचती है जब उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति सार्वजनिक रूप से अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायमूर्तियों पर अविश्वास जताते हैं, तो । यह बात बार-बार कही गई है कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान असभ्य भाषा का इस्तेमाल करके और अधीनस्थ न्यायपालिका पर आरोप लगाकर हासिल नहीं किया जा सकता। जिस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ फैसले में बातें कही गई हैं, वह अपने आदेश का बचाव करने के लिए ऊँची अदालत के सामने पेश नहीं हो सकता। इसलिए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को ज़्यादा न्यायिक संयम बरतना चाहिए और जब वे अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने का मन करें, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। [426-जी-एच]

4.1. किसी न्यायिक आदेश के समर्थन में कारण सिर्फ़ आदेश में ही लिखे जा सकते हैं और किसी न्यायिक अधिकारी को बाद में अपने फैसले के बचाव में प्रतिवेदन लिखने के लिए मजबूर करना एक गलत तरीका है। [422-एच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 200/1997।

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 5.11.96 के निर्णय और आदेश से, आपराधिक विविध संख्या 10564/1996 में।

अपीलकर्ता के लिए एल.आर. सिंह।

उत्तरदाता संख्या 4 के लिए उदय सिंह और ए.के. झा।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा सुनाया गया

थॉमस, न्यायमूर्ति अनुमति दी गई।

न्यायिक संयम एक गुण है। एक ऐसा गुण जो हर न्यायिक फैसले के साथ होना चाहिए। यह एक न्यायमूर्ति का गुण है जिसे उसे समय-समय पर बनाए रखना होता है, खासकर जब वह अपने सामने आने वाले मामलों से निपट रहा हो, चाहे वह अपीलीय, पुनरीक्षण या अन्य पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर रहा हो। उच्च न्यायालयों को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि न्यायिक पदानुक्रम में उच्च स्तर इसलिए दिए गए हैं ताकि निचले स्तर के न्यायालयों के फैसलों या आदेशों में हुई गलतियों को सुधारा जा सके। ऐसी शक्तियां निश्चित रूप से निचले स्तर के न्यायिक व्यक्तियों पर कड़वी आलोचना करने के लिए नहीं हैं। एक न्यायविद के शब्दों को याद रखना अच्छा है कि "जिस न्यायमूर्ति ने कोई गलती नहीं की है, वह अभी पैदा होना बाकी है"।

उपरोक्त प्रस्तावनात्मक शब्दों को कहने का संदर्भ यह है कि अपीलकर्ता ब्रज किशोर ठाकुर, जो बिहार न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति हैं, द्वारा व्यक्त की गई उस शिकायत से संबंधित है, जो पटना उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायमूर्ति द्वारा उनके विरुद्ध की गई तीखी और कठोर फटकार को लेकर है। यह फटकार उस आदेश में की गई थी, जिसमें एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 20(बी)(i) के तहत अपराध में संलिप्त दो आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द किया गया था। विचलित सत्र न्यायमूर्ति ने उन अवमाननापूर्ण टिप्पणियों को हटवाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, परंतु उन्हें हटाने के बजाय माननीय एकल न्यायमूर्ति ने उसी अवसर का उपयोग करते हुए उन निंदात्मक टिप्पणियों को और अधिक कठोरता के साथ दोहराया। अतः उक्त सत्र न्यायमूर्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में आए हैं। हमने उन्हें विशेष अनुमति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि इस प्रकार है: 16.2.1995 को बिहार में कुछ सीमा-शुल्क अधिकारियों ने फहेंगोला (किशनगंज) में एक एम्बेसडर कार को रोका और उसकी तलाशी ली, जिसमें वाहन के अंदर बनाए गए एक नकली खाने में 97 किलोग्राम "शुल्क-अदा न किया गया गाँजा"

छिपा हुआ पाया गया। कार के चालक और दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लगभग तीन महीने बाद उन तीनों व्यक्तियों ने जमानत के लिए आवेदन किया और वह आवेदन अपीलकर्ता के समक्ष आया, जो उस समय सत्र न्यायमूर्ति-सह-विशेष न्यायमूर्ति, पूर्णिया थे।

उन्होंने 29.7.1995 को आदेश पारित किया जिसमें चालक की जमानत अस्वीकार कर दी गई और अन्य दो व्यक्तियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। इस आदेश को सीमा शुल्क संग्राहक, पटना ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी। माननीय एकल न्यायमूर्ति (नारायण रॉय, ज.) ने अपीलकर्ता से यह पूछते हुए एक प्रतिवेदन मंगाई कि किन परिस्थितियों में जमानत दी गई थी। (हम यह समझने में असमर्थ हैं कि माननीय एकल न्यायमूर्ति किसी अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी से उसके न्यायिक आदेश के समर्थन में प्रतिवेदन भेजने के लिए कैसे कह सकते थे। किसी न्यायिक आदेश के समर्थन में कारण केवल उसी आदेश में प्रकट हो सकते हैं, और किसी न्यायिक अधिकारी को अपनी निष्कर्षों के समर्थन में बाद में प्रतिवेदन लिखने के लिए बाध्य करना एक अवांछनीय प्रथा है।) जैसा भी हो — माननीय एकल न्यायमूर्ति ने प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद उन दो व्यक्तियों को दी गई जमानत रद्द करने का आदेश पारित किया और उस आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं, जो अब इस अपील का विषय बन गई हैं।

> "अतः माननीय विशेष न्यायमूर्ति को इस कठोर कानून को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त विपक्षी पक्षकारों को जमानत देने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और जब जब्त किया गया मादक पदार्थ भारी मात्रा में था, तो वाद को गंभीर दृष्टि से देखा जाना चाहिए था और अभियुक्तों द्वारा लिए गए तर्क पर विश्वास करते हुए इतनी आसानी से जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी।"
>
> "...मुझे प्रतीत होता है कि जमानत बाहरी विचारों के आधार पर दी गई है।"

"इस आदेश को समाप्त करने से पहले, मैं यह अवलोकन करना चाहूँगा कि माननीय विशेष न्यायमूर्ति, जो कि वरिष्ठतम सत्र न्यायमूर्ति भी हैं, वे धारा 37, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करते हुए इतने सहज ढंग से आक्षेपित आदेश पारित नहीं कर सकते थे। अभियुक्त विपक्षी पक्षकार संख्या 1 और 2 को जमानत देने का माननीय विशेष न्यायमूर्ति का कार्य न्यायिक अविवेक का द्योतक है और उनकी अपनी प्रतिवेदन में दर्शाए गए इस स्वीकार के मद्देनज़र कि वे इस संबंध में कानून से अवगत नहीं थे, वे सत्र न्यायमूर्ति बने रहने के योग्य नहीं हैं और उनसे उनकी मूल शक्तियाँ वापस ले ली जानी चाहिएँ। अतः मैं इस वाद को गंभीरता से लेता हूँ और अपनी अप्रसन्नता अभिलेख में दर्ज करता हूँ।"

जब अपीलकर्ता ने उपरोक्त टिप्पणियों को हटाने के लिए आवेदन किया, तो माननीय एकल न्यायमूर्ति ने उन्हें पुनः दोहराया और आगे यह भी जोड़ा :

"20.5.1996 का आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं, स्वयं स्पष्ट है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध बहुत कुछ कहता है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को अवांछित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे इस वाद के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में की गई थीं, जहाँ याचिकाकर्ता ने कानूनी मानकों को नज़रअंदाज़ करते हुए वाद के साथ अत्यंत लापरवाही और सहजता से व्यवहार किया और अभियुक्तों को जमानत प्रदान कर दी।"

माननीय एकल न्यायमूर्ति ने आगे यह भी जोड़ा :

"इस न्यायालय का यह अवलोकन कि माननीय विशेष न्यायमूर्ति ने बाहरी विचारों के आधार पर जमानत दी थी, इसलिए, मेरी राय में, इस न्यायालय के निष्कर्षों के अनुरूप है और बाहरी विचारों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।"

अपीलकर्ता की शिकायत पर विचार करने से पहले, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के दो प्रासंगिक प्रावधानों पर एक दृष्टि डालना उपयोगी होगा। अधिनियम की धारा 20(b)(i) के अंतर्गत अपराध इस प्रकार है :

"जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या दिए गए किसी लाइसेंस की शर्त के उल्लंघन में—

(क)....

(ख) भांग का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, *अंतर-राज्यीय* आयात, *अंतर-राज्यीय* निर्यात या उपयोग करता है, वह दंडनीय होगा—

(i) जहाँ ऐसा उल्लंघन गाँजा या भांग के पौधे की खेती से संबंधित हो, वहाँ उसे ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो पाँच वर्ष तक की अवधि का हो सकता है और साथ ही उस पर पचास हज़ार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"

धारा 37(1)(ख) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्तियों को जमानत देने में न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 37(1) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है :

"भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद-

(ख) इस अधिनियम के तहत पाँच वर्ष या उससे अधिक कारावास योग्य अपराध में आरोपित किसी भी व्यक्ति को जमानत या अपने बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(i) लोक अभियोजक को ऐसे रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय यह संतुष्ट न हो कि ऐसे अपराध में उस पर दोष नहीं मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं और कि जमानत पर रहते हुए वह किसी अपराध को दोबारा नहीं करेगा।"

इस न्यायालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम किशन लाल एवं अन्य, एआईआर (1991) एससी 558 में यह अवलोकन किया कि उच्च न्यायालय की शक्ति, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत है, भी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 में निहित सीमाओं के अधीन है।

चूंकि माननीय एकल न्यायमूर्ति द्वारा जमानत रद्द करने का आदेश हमारे समक्ष अपील में नहीं है, इसलिए हमें आदेश के कार्यकारी भाग की शुद्धता या अशुद्धता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि अब हम अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई विवादास्पद टिप्पणियों की न्यायसंगतता से संबंधित हैं, इसलिए हम उनके अपने आदेश के बचाव में अपनाए गए रुख का उल्लेख करना उचित समझते हैं। उन्होंने हमारी ध्यानाकर्षण इस निर्णय की ओर करवाया: पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा कमलेश कुमार बनाम राज्य बिहार, (1994) 2 पीएलजेआर 600 में दिया गया निर्णय, जिसमें यह कहा गया है कि "जब किसी अभियुक्त पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(i) के तहत आरोप लगाया गया हो, तो धारा 37(1)(ख) के अंतर्गत शक्ति लागू नहीं होती।" उस निर्णय में खंड पीठ ने इस न्यायालय के किशन लाल के वाद (उपरोक्त) के निर्णय का भी संदर्भ दिया।

हालाँकि इस अपील में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा स्थापित उक्त नियम की शुद्धता पर विचार करने का अवसर नहीं है, हमें यह अवलोकन करना होगा कि बिहार राज्य की सभी अधीनस्थ न्यायालयें कमलेश कुमार के वाद में स्थापित कानूनी स्थिति के पालन के लिए बाध्य हैं। हमें इस न्यायालय के किसी भी ऐसे निर्णय की जानकारी नहीं है

जो इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाता हो, और इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों पर उक्त निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को अत्यधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम यह मान नहीं सकते कि माननीय एकल न्यायमूर्ति उस कानूनी स्थिति से अनभिज्ञ थे, जिसे उसी उच्च न्यायालय ने स्थापित किया था, यद्यपि उन्होंने न तो जमानत रद्द करने वाले अपने आदेश में और न ही टिप्पणियाँ हटाने से इंकार करने वाले अपने पश्चात आदेश में इसका कोई उल्लेख किया। जब माननीय एकल न्यायमूर्ति ने अपीलकर्ता की आलोचना करते हुए कहा कि वह "कानून से अनभिज्ञ था और नवीनतम निर्णयों से अवगत नहीं था," तो यह अपेक्षित होता कि माननीय एकल न्यायमूर्ति स्वयं को उसी उच्च न्यायालय द्वारा उसी विषय पर स्थापित कानूनी स्थिति की याद दिलाते। यदि बिहार में अधीनस्थ न्यायपालिका पर बाध्यकारी कानून की स्थिति यही थी (जैसा कि खंड पीठ ने कमलेश कुमार बनाम राज्य बिहार में स्थापित किया), तो उसी उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायमूर्ति द्वारा यह कहना कि अपीलकर्ता विशेष न्यायमूर्ति ने जमानत देने में अपनी क्षेत्राधिकार सीमा से अधिक कार्य किया, बिल्कुल भी उचित नहीं था।

हमें इसमें कोई संकोच नहीं कि सत्र न्यायमूर्ति पूरी तरह अपनी क्षेत्राधिकार सीमा के भीतर थे जब उन्होंने उन दो व्यक्तियों को जमानत देने का आदेश पारित किया, यद्यपि यह अलग बात है कि उन्होंने विवेक का सही प्रयोग किया या नहीं।

जब अपीलकर्ता ने माननीय एकल न्यायमूर्ति के समक्ष यह याचिका दायर की कि न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध अत्यंत अपमानजनक आरोप "मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जमानत बाहरी विचारों के आधार पर दी गई है" को हटाया जाए, तो निष्पक्षता की आवश्यकता थी कि जब उन्होंने उन टिप्पणियों को अब चुनौती में आए आदेश में दोहराया, तो कम से कम अपने कारण प्रस्तुत करें। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है—हम कह सकते हैं कि अत्यंत पीड़ादायक—है कि माननीय एकल न्यायमूर्ति ने बिना किसी औचित्य के उन अत्यंत अवमाननापूर्ण टिप्पणियों को दोहराना जारी रखा।

अपीलकर्ता के अनुसार, उन्होंने 30 वर्षों से अधिक का न्यायिक सेवा अनुभव अर्जित किया है, और उन्हें एक स्तर से उच्चतर स्तर में पदोन्नत किया गया, तथा 1992 में उन्हें

जिला एवं सत्र न्यायमूर्ति के रूप में पदोन्नत किया गया और 1995 में उन्हें सुपर-टाइम स्केल वेतन प्रदान किया गया। उन्होंने अपने गहन मानसिक दुख को व्यक्त किया जब उन्हें ऐसे कठोर फटकारों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके अधीनस्थों की दृष्टि में ही नहीं, बल्कि जनता की दृष्टि में भी उन्हें सदा के लिए दोषी ठहरा दिया गया। यह केवल उनका ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका की छवि को भी ऐसे कठोर आरोपों से धूमिल कर दिया गया।

न्यायपालिका के संचालन और जनता के न्यायिक संस्थाओं में विश्वास को इससे बड़ा नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता कि जब उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति सार्वजनिक रूप से अधीनस्थ न्यायमूर्तियों में विश्वास की कमी व्यक्त करें। बार-बार यह कहा गया है कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान अतिव्यक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग करके और अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगाकर अर्जित नहीं किया जा सकता। यह याद रखना आवश्यक है कि जिस न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध निर्णय में आरोप लगाए गए हैं, वह अपने आदेश का बचाव करने के लिए उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए, ऊपरी न्यायालयों के न्यायमूर्तियों को ज़्यादा न्यायिक संयम बरतना चाहिए और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, जब वे अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ़ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं।

पच्चीस साल पहले, गजेंद्रगडकर, न्यायमूर्ति (जैसा कि वे उस समय थे) ने इस न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियों की बेंच की ओर से बोलते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के खिलाफ़ की गई कड़ी टिप्पणियों (यह सुझाव देते हुए कि उनका फैसला बाहरी विचारों पर आधारित था) के संदर्भ में, अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ़ कड़ी भाषा का इस्तेमाल करने और भ्रष्ट इरादों का आरोप लगाने के खिलाफ़ अत्यधिक न्यायिक संयम बरतने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, खासकर "क्योंकि जिस न्यायमूर्ति पर आरोप लगाए गए हैं, उसके पास कानून में अपनी स्थिति साबित करने का कोई उपाय नहीं है" (ईश्वरी प्रसाद मिश्रा बनाम मोहम्मद ईसा, [1963] 3 एससीआर 722)। इस न्यायालय को बाद में भी ऐसे शब्द दोहराने पड़े। के.पी. तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य,

एआईआर (1994) एससी 1031 में इस न्यायालय के सामने उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायमूर्ति की कुछ टिप्पणियां आईं, जिसमें उन्होंने अधीनस्थ न्यायपालिका के एक न्यायमूर्ति के खिलाफ़ कड़ी टिप्पणियां की थीं और न्यायालय ने इस मौके का इस्तेमाल सभी संबंधित लोगों को यह याद दिलाने के लिए किया कि अनियंत्रित भाषा का इस्तेमाल करने और निचले स्तर पर कड़ी टिप्पणियां करने से न्यायपालिका में जनता का सम्मान कम होगा। इस संदर्भ में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को दोहराने की ज़रूरत है:

> "उच्च न्यायालय प्रतिदिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऐसे आदेशों का सामना करते हैं जो न तो कानून के अनुसार और न ही तथ्य के अनुसार न्यायोचित हैं, और उन्हें संशोधित या रद्द कर देते हैं। यही उच्च न्यायालयों के कार्यों में से एक है। हमारा कानूनी तंत्र न्यायमूर्तियों की त्रुटिपूर्णता को स्वीकार करता है और इसलिए अपील और पुनरीक्षण की व्यवस्था करता है। एक न्यायमूर्ति अपनी क्षमतानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करता है। ऐसा करते समय, कभी-कभी वह त्रुटि कर सकता है... यह भी याद रखना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी अधिकांशतः तनावपूर्ण वातावरण में काम करते हैं और लगातार मानसिक दबाव में रहते हैं, जिसमें सभी उत्तरदाता और उनके वकील लगभग उनके ऊपर सांस ले रहे होते हैं, अधिक सटीक रूप से कहें तो उनकी नाक तक। उन्हें उच्च न्यायालय के अलग वातावरण का लाभ नहीं मिलता जिसमें वे ठंडे दिमाग से सोच सकें और धैर्यपूर्वक निर्णय ले सकें। इसलिए, प्रत्येक त्रुटि, चाहे वह कितनी भी गंभीर प्रतीत हो, उसे अनुचित उद्देश्य का परिणाम नहीं मानना चाहिए।"

हाल ही में, *काशी नाथ रॉय बनाम बिहार राज्य*, जेटी (1996) 4 एससी 605 वाद में, हमने इसी तरह की स्थिति में, हालांकि अलग शब्दों में, यही बात कही थी। तब हमने इस तरह कहा था:

"यह नहीं भुलाया जा सकता कि हमारे तंत्र में, अन्यत्र की तरह, अपील और पुनरीक्षण न्यायालय इस पूर्वधारण पर स्थापित किए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय कुछ मामलों में निर्णय लेने में त्रुटि कर सकते हैं, चाहे वह तथ्य पर हो या कानून पर, और इन्हें उन आदेशों को सुधारने के लिए जोड़ा गया है। न्यायिक प्रक्रिया में मानवीय तत्व एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए न्यायालयों से कम्प्यूटर जैसी निष्पक्ष कार्यक्षमता की अपेक्षा नहीं की जा सकती; चाहे वे कितनी भी मेहनत करें और स्वयं को न्यायिक विवेक के दायरे और न्याय करने के तरीके में पूर्वनिर्धारित रखें। जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी असहनीय त्रुटि का पता लगाया जाता है या उसे इंगित किया जाता है, तो उसे उस त्रुटि को सुधारने का कर्तव्य होता है और उपयुक्त मामलों में, न्यायालय की गरिमा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए, अपने निर्णय में संबंधित अधिकारी को संदेश पहुँचाया जा सकता है, जो तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, नम्र लेकिन स्पष्ट और परिणाम-उन्मुख हो, परन्तु बहुत कम ही यह आलोचना के रूप में हो। इस प्रकार की तीव्र प्रतिक्रिया, जैसा कि पूर्वोक्त उद्धरण में दिखाया गया है, संस्थागत कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है। यह पूर्वधारणा कि किसी न्यायमूर्ति ने अस्वीकार्य सीमा से परे त्रुटि की है, अधीनस्थ न्यायमूर्ति पर निंदा थोपने का कारण नहीं बनती—जब तक कि कोई अन्य असाधारण आधार मौजूद न हो।"

हमें खेद है कि माननीय एकल न्यायमूर्ति ने ऊपर बताई गई सावधानियों को, जिन्हें बार-बार दोहराया गया है, अपने ध्यान में नहीं रखा। जब उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के एक 'अप्रतिबद्ध' न्यायमूर्ति के विरुद्ध अनुचित, अप्रिय और तीखी टिप्पणियाँ कीं, तो उन्होंने केवल न्यायपालिका संस्थान को ही चोट पहुँचाई।

न्याय और निष्पक्षता के हित में, हम 20.5.1996 के आदेश में अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई सभी आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटा देते हैं।

तदनुसार अपील का निष्पादन किया जाता है।

पी टी डी। अपील का निपटारा किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।